

मुकदमों का विवरण

एसआरआई। के. एम. कृष्णा रेड्डी बनाम

एसआरआई। वाइन रेड्डी और ए. एन. आर. (2010 की सिविल अपील संख्या 4471)
अक्टूबर 06, 2023

[अभय एस. ओका और पंकज मिट्टल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: जब स्वामित्व के आधार पर एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद सरलीकरण में, प्रतिवादी वादी या उसके पूर्ववर्ती के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे द्वारा अपने अधिकार की पूर्णता का अनुरोध करता है, तो क्या वादी के लिए स्वामित्व की घोषणा का दावा करना आवश्यक है।

मुकदमा-मालिकाना हक के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए-प्रतिवादी द्वारा अनुरोध किए गए प्रतिकूल कब्जे द्वारा मालिकाना हक की पूर्णता-यदि वादी के लिए मालिकाना हक की घोषणा का दावा करना आवश्यक है:

आयोजित किया गया: प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी के पिता के स्वामित्व को स्वीकार किया जिसके माध्यम से अपीलार्थी ने अधिकार का दावा किया-यहां तक कि प्रत्यर्थियों के मामले को देखते हुए भी, अपीलार्थी संपत्ति का सह-मालिक था, और प्रत्यर्थियों का स्वीकार है कि मुकदमे की संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार नहीं था-इस प्रकार, वादी और उसके पिता के अधिकार के बारे में कोई मुद्दा शामिल नहीं था-ऐसा नहीं है कि प्रत्यर्थियों ने अपने आप में एक अधिकार स्थापित किया था या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा कर रहे थे जो अधिकार का दावा कर रहा था-उनकी याचिका अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे की थी, जो यह मानती है कि अपीलार्थी मालिक था-जब एक मुकदमे में शीर्षक के आधार पर एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए, प्रतिवादी अभियोग के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे द्वारा अपने अधिकार की पूर्णता का अनुरोध करता है।

210

एसआरआई। के. एम. कृष्णा रेड्डी बनाम श्री। वाइन रेड्डी और ए. एन. आर.

उनका शीर्षक-इसलिए, मुकदमा, जैसा कि मूल रूप से किया गया था, बनाए रखने योग्य था-प्रतिवादियों पर प्रतिकूल कब्जे की अपनी याचिका को साबित करने का बोझ था, क्योंकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा की मांग करने वाला एक प्रति-दावा (जो एक प्रति-मुकदमे की प्रकृति में है) था-उच्च न्यायालय ने केवल एक मुद्दे का फैसला किया कि क्या अपीलकर्ता द्वारा स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए अनुरोध के लिए मांगे गए संशोधन को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था-क्योंकि उच्च न्यायालय ने मुकदमे के गुण-दोष पर विचार नहीं

किया और प्रति-दावा, उच्च न्यायालय में नियमित रूप से भेजी गई दूसरी अपील-विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-उच्च न्यायालय के प्रति नियमित दूसरी अपील को बहाल कर दिया गया-प्रतिकूल कब्जा।[पैरा 14,16,18,20 और 21]

प्रतिकूल कब्जा-याचिका-जब हार जाती है-दो वैकल्पिक याचिकाएं-अपीलार्थी द्वारा दायर अधिकार के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा, उत्तरदाताओं ने प्रतिकूल कब्जे द्वारा अधिकार की पूर्णता का अनुरोध किया-उत्तरदाताओं ने हालांकि वाद संपत्ति के लिए अपीलार्थी के पिता का खिताब स्वीकार किया, उन्होंने विवाद किया कि वाद संपत्ति पारिवारिक समझौते के तहत अपीलार्थी के हिस्से को आवंटित की गई थी और दावा किया कि अपीलार्थी का भाई 'जे' विभाजन में वाद संपत्ति का आवंटनकर्ता था और उत्तरदाता की मां को उनकी मां के पक्ष में बिक्री के समझौते के आंशिक प्रदर्शन में 'जे' द्वारा वाद संपत्ति के कब्जे में रखा गया था:

आयोजित किया गया:यह विवाद प्रतिकूल कब्जे की याचिका के खिलाफ पूरी तरह से विरोध करता है क्योंकि यह प्रतिकूल कब्जे की याचिका को पूरी तरह से विफल कर देता है-यह तर्क दर्शाता है कि प्रतिवादी शत्रुतापूर्ण कब्जे का दावा नहीं कर रहे हैं, जो प्रतिकूल कब्जे की याचिका का एक आवश्यक घटक है-परीक्षण स्तर पर, उत्तरदाताओं को दो वैकल्पिक याचिकाओं में से एक को चुनना चाहिए था-हालांकि, परीक्षण न्यायालय द्वारा बनाए गए मुद्दों से संकेत मिलता है कि उत्तरदाताओं ने प्रतिकूल कब्जे की याचिका के साथ-साथ उक्त 'जे' द्वारा निष्पादित बिक्री के समझौते के आधार पर उनकी याचिका पर भरोसा किया-इसके अलावा, उत्तरदाताओं द्वारा अनुरोध किया गया विभाजन का विलेख, जिसके आधार पर, उनके अनुसार, 'जे' मालिक बन गया था, स्वीकार्य रूप से साबित नहीं हुआ था-वास्तव में, लिखित बयान में, विभाजन के नंगे विवरण जिसके आधार पर 'जे'[पैरा 13]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

अनाथुला सुधाकर बनाम पी. बुची रेड्डी (मृत) एल. आर. एस. और अन्य (2008)

4 एससीसी 594:[2008] 5 एस. सी. आर. 331-पर निर्भर।

212

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2010 की सिविल अपील सं. 4471।2007 के आर. एस. ए. No.1361 में बेंगलूर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.02.2010 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

रोहन दीवान, बालाजी श्रीनिवासन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अमित आनंद तिवारी, सुश्री शकुन शर्मा, सुश्री देवयानी गुप्ता, सुश्री तन्वी आनंद, अनिरुद्ध सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अभय एस. ओकेए, जे.

वास्तविक पहलू

1. मूल वादी ने दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए इस अपील को प्राथमिकता दी है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को रद्द कर दिया है।

प्लेट

2. अपीलार्थी ने वादी की अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित अचल संपत्ति के संबंध में एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद का नेतृत्व किया (संक्षेप में, 'वाद संपत्ति')।अपीलार्थी के अनुसार, वह और उसके भाई अपने पिता की मृत्यु के बाद मुकदमे की संपत्ति में सफल हुए।उन्होंने दावा किया कि मुकदमे की संपत्ति 25 अप्रैल 1993 को एक पारिवारिक समझौते के तहत उनके हिस्से में आवंटित की गई थी, जिसे उनके और उनके भाइयों के बीच निष्पादित किया गया था। अपीलार्थी दावा करता है कि उसके पास मुकदमे की संपत्ति का अनन्य अधिकार है।मुकदमा कार्रवाई के कारण पर आधारित है कि 18 जून 1994 को, प्रत्यर्थियों ने मुकदमे की संपत्ति पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोशिश की।इसलिए, निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा सरलीकरण उनके नेतृत्व में किया गया था।

लिखित कथन के साथ-साथ दावा

3. प्रतिवादियों ने एक लिखित बयान और जवाबी दावे का नेतृत्व किया जिसमें स्वीकार किया गया कि मुकदमे की संपत्ति मूल रूप से श्री के स्वामित्व में थी।

213

एसआरआई. के. एम. कृष्णा रेड्डी बनाम श्री। वाइन रेड्डी और ए. एन. आर. [अभय एस. ओकेए, जे.] 214

अपीलार्थी के दिवंगत पिता मुनिस्वमप्पा।लिखित बयान में उत्तरदाताओं का तर्क था कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ 1978 से लगातार सूट संपत्ति के कब्जे में थे और लकड़ी, ईंटों और खाद का भंडारण कर रहे थे।उनके मामले के अनुसार, वे 1978 से मुकदमे की संपत्ति का निर्बाध रूप से उपयोग कर रहे हैं, और उन्होंने अपीलार्थी, उनके पिता और उनके भाई एम. जयराम रेड्डी (संक्षेप में, 'जयराम') सहित उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी के साथ

ऐसा किया है। इसलिए, उत्तरदाताओं ने दावा किया कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे द्वारा मुकदमा संपत्ति के अधिकार को पूर्ण कर दिया था।

4. प्रत्यर्थियों द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि अपीलार्थी के पिता की मृत्यु के बाद हुए विभाजन में मुकदमे की संपत्ति जयराम के हिस्से को आवंटित की गई थी। अक्टूबर 1983 में, उक्त जयराम ने अपनी माँ से संपर्क किया और कहा कि यदि उन्हें भुगतान किया जाता है, तो प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। उत्तरदाताओं के अनुसार, उनकी माँ ने जयराम को 5,500/- रुपये की राशि का भुगतान किया, जिन्होंने उनकी माँ के पक्ष में बिक्री के लिए एक समझौते को निष्पादित किया। यह भी तर्क दिया गया कि बिक्री के लिए समझौते के आंशिक प्रदर्शन में, उत्तरदाता की माँ को सूट संपत्ति के कब्जे में रखा गया था। लिखित बयान में यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी ने अपने भाई जयराम के साथ मिलकर मुकदमा दायर किया था।

5. उत्तरदाताओं द्वारा एक जवाबी दावा किया गया था जिसमें एक घोषणा का दावा किया गया था कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से सूट संपत्ति पर अपने अधिकार को पूरा कर लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 25 अप्रैल 1993 का पारिवारिक समझौता, जिस पर अपीलार्थी ने भरोसा किया था, अमान्य और गैर-कानूनी था।

मैदान में सुधार

6. अपीलार्थी ने 11 नवंबर 1997 को पैराग्राफ 4 (ए) को शामिल करने के लिए शिकायत में संशोधन करने और स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए अनुरोध करने के लिए आवेदन किया। ट्रायल कोर्ट ने 04 जून 1998 के आदेश द्वारा संशोधन की अनुमति दी। संशोधन की अनुमति के बाद, प्रत्यर्थियों ने एक अतिरिक्त लिखित बयान का नेतृत्व किया, जिसमें तर्क दिया गया कि अपीलार्थी संशोधन द्वारा अपने मामले में सुधार नहीं कर सकता है।

न्यायालयों के निष्कर्ष

7. ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया और जवाबी दावे का फैसला सुनाया। अपीलार्थी द्वारा दायर एक अपील में, जिला न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

अपीलार्थी के नेतृत्व में मुकदमा दायर किया। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए हस्तक्षेप किया कि घोषणा के लिए प्रार्थना को शामिल करने वाला संशोधन सीमितता से वर्जित था और यह कि यह मुकदमा शुरू होने की तारीख से संबंधित नहीं होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने किसी अन्य मुद्दे पर विचार नहीं किया।

प्रस्तुतियाँ

8. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुतिकरण यह था कि अपीलार्थी के शीर्षक के संबंध में सभी सामग्री विवरण पहले से ही वाद में शामिल किए गए थे जैसा कि मूल रूप से निर्धारित किया गया था, और केवल प्रचुर सावधानी के माध्यम से शीर्षक की घोषणा के लिए एक प्रार्थना को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। उनका निवेदन है कि प्रार्थना पहले से ही शिकायत में निहित थी जैसा कि मूल रूप से किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी के अधिकार को स्वीकार किया, यह जांच किए बिना कि क्या प्रत्यर्थियों ने प्रतिकूल अधिकार की अपनी याचिका स्थापित की थी, उच्च न्यायालय ने मुकदमे को खारिज करके प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश में गलती से हस्तक्षेप किया था।

9. प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने आग्रह किया कि शिकायत में दी गई कार्रवाई का कारण शुरू में 18 जून 1994 को सामने आया था। उन्होंने आग्रह किया कि चूंकि अपीलार्थी के अधिकार के बारे में एक गंभीर विवाद था, इसलिए अधिकार की घोषणा के बिना मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था। उन्होंने बताया कि संशोधन के लिए आवेदन 11 नवंबर 1997 को सीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में, 'सीमा अधिनियम') के अनुच्छेद 58 के तहत प्रदान की गई सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद पेश किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार संशोधन को समय की पाबंदी के रूप में आयोजित किए जाने के बाद मुकदमा विफल होना चाहिए।

प्रस्तुतियों का समावेश

10. हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है। जैसा कि मूल वाद और पैराग्राफ 3 में किए गए अभिकथनों से देखा जा सकता है, मुकदमा शीर्षक पर आधारित था, जैसा कि अपीलार्थी ने निर्धारित किया है कि वह किस आधार पर पूर्ण स्वामित्व का दावा कर रहा था। एक आरोप है कि प्रत्यर्थियों के पास कोई अधिकार नहीं है और अपीलार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

11. प्रत्यर्थियों के नेतृत्व में लिखित बयान के पैराग्राफ 9 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि अपीलार्थी के पिता मुकदमे की संपत्ति के मालिक थे। यह आग्रह किया गया कि उत्तरदाताओं के पिता और उसके बाद, उत्तरदाताओं के पास मुकदमे का खुला और शांतिपूर्ण कब्जा हो 215

एसआरआई. के. एम. कृष्णा रेड्डी बनाम श्री। वाइन रेड्डी और ए. एन. आर. [अभय एस. ओका, जे.] 216

1978 से संपत्ति और प्रतिकूल कब्जे द्वारा अपने खिताब को परिपूर्ण किया है। एक असंगत याचिका ली गई कि अपीलार्थी के भाई जयराम को विभाजन में वाद संपत्ति मिली थी और उक्त जयराम द्वारा उनकी माँ के पक्ष में बिक्री के लिए एक समझौता किया गया था। वास्तव में, उन्होंने

दावा किया कि उनकी माँ को समझौते के आंशिक प्रदर्शन में सूट संपत्ति के कब्जे में रखा गया था।

12. इस प्रकार, प्रत्यर्थियों ने वाद संपत्ति में अपीलार्थी के पिता की उपाधि को स्वीकार किया। प्रत्यर्थियों द्वारा जिस बात पर विवाद किया गया था, वह अपीलार्थी का दावा था कि मुकदमे की संपत्ति 25 अप्रैल 1993 के पारिवारिक समझौते के तहत उसके हिस्से को आवंटित की गई थी। इस प्रकार, भले ही पारिवारिक निपटान के दस्तावेज को नजरअंदाज कर दिया जाए, अपीलार्थी अपने पिता की मृत्यु के बाद मुकदमे की संपत्ति के सह-मालिकों में से एक था। हालाँकि प्रत्यर्थियों ने दावा किया कि अपीलार्थी के भाई जयराम विभाजन में वाद संपत्ति के आवंटनकर्ता थे, लेकिन प्रत्यर्थियों ने विभाजन को साबित नहीं किया। वे यह स्थापित नहीं कर सके कि सूट की संपत्ति उक्त जयराम के हिस्से में आई थी। उच्चतम स्तर पर, उत्तरदाताओं ने साबित किया कि जयराम द्वारा निष्पादित बिक्री समझौते के तहत, उनकी माँ ने उक्त जयराम को ध्यान में रखा। हालाँकि, लिखित कथन सह प्रति-दावे में, एक विशिष्ट सी अभिवचन है जो निम्नानुसार है:

“इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने अधिकार को पूरा किया है, कुछ शुभचिंतकों की सलाह पर उनकी माँ ने रु। 5, 500/- संपत्ति पर पूर्ण विचार के लिए और रेड्डी ने बिक्री का एक समझौता किया और कब्जे को जारी रखने के लिए सहमति दी और उक्त समझौते में कब्जा स्वीकार कर लिया गया। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बेचने के समझौते के एक भाग प्रदर्शन के रूप में, प्रतिवादी की माँ को उसी के कब्जे में रखा गया है।”

(आपूर्ति की गई रेखाएँ) 13। इस प्रकार, स्थिति यह है कि उनकी माँ को जयराम द्वारा बिक्री के लिए समझौते के आंशिक प्रदर्शन में सूट संपत्ति के कब्जे में रखा गया था। यह विवाद पूरी तरह से प्रतिकूल कब्जे की याचिका के खिलाफ है क्योंकि यह विवाद प्रतिकूल कब्जे की याचिका को पूरी तरह से विफल कर देता है। कारण यह है कि यह तर्क दर्शाता है कि उत्तरदाता शत्रुतापूर्ण कब्जे का दावा नहीं कर रहे हैं, जो प्रतिकूल कब्जे की याचिका का एक आवश्यक घटक है। वास्तव में, परीक्षण स्तर पर, उत्तरदाताओं को चुना जाना चाहिए था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

दो वैकल्पिक दलीलों में से एक। हालांकि, निचली अदालत द्वारा बनाए गए मुद्दों से संकेत मिलता है कि प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे की अपनी याचिका के साथ-साथ उक्त जयराम द्वारा निष्पादित बिक्री के समझौते के आधार पर अपनी याचिका पर भरोसा किया। इस प्रकार, प्रत्यर्थियों के लिखित बयान में लिए गए रुख के अनुसार, उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलार्थी के पिता मुकदमे की संपत्ति के मालिक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद, अपीलार्थी अपने भाइयों के साथ सह-मालिकों में से एक बन गया। प्रत्यर्थियों द्वारा अनुरोध किया गया विभाजन का विलेख, जिसके आधार पर, उनके अनुसार, जयराम मालिक बने, स्वीकार्य रूप से साबित नहीं

हुआ है। वास्तव में, लिखित बयान में, जिस विभाजन के आधार पर जयराम मालिक बने, उसके बारे में उत्तरदाताओं ने कुछ भी नहीं कहा था। अभिवचनों का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“प्रतिवादियों का कहना है कि मुनिस्वामप्पा की मृत्यु के बाद, वादी और उसके भाइयों ने अपनी संपत्तियों का विभाजन कर दिया है और विचाराधीन संपत्ति M.Jayaram रेड्डी को आवंटित की गई थी, हालांकि उस पर उनका कब्जा नहीं था।”

14. इसलिए, प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी के पिता के स्वामित्व को स्वीकार किया, जिनके माध्यम से अपीलार्थी अधिकार का दावा करता है। यहां तक कि प्रत्यर्थियों के मामले को देखते हुए, अपीलकर्ता संपत्ति का सह-मालिक था, और प्रत्यर्थियों के पास मुकदमे की संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, अपीलार्थी के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं था जैसा कि मुकदमे में कहा गया था। मुद्दा यह था कि क्या प्रतिकूल कब्जे की याचिका ने उस खिताब को हरा दिया। प्रतिकूल कब्जे की याचिका को साबित करने का भार प्रत्यर्थियों पर था। अपीलार्थी पर मुकदमे की तारीख को अपना अधिकार साबित करने का बोझ था। 15. सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी के लिए अधिकार की घोषणा का दावा करना आवश्यक था। इस पहलू पर, के मामले में इस न्यायालय का एक निर्णय

अनाथुला सुधाकर बनाम पी. बुची रेड्डी (मृत) एलआरएस द्वारा। और अन्य 1 है

प्रासंगिक। उक्त निर्णय का पैरा 13 और 14 इस प्रकार है: “13. स्थायी निषेधाज्ञा के लिए केवल मुकदमा कब होगा, और घोषणा के लिए मुकदमा दायर करना और/या परिणामी राहत के रूप में निषेधाज्ञा के साथ कब्जा करना कब आवश्यक होगा, इस बारे में सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं। हम उन्हें संक्षेप में संदर्भित कर सकते हैं।

1 (2008) 4 एससीसी 594 217

एसआरआई. के. एम. कृष्णा रेड्डी बनाम श्री। वाइन रेड्डी और ए. एन. आर. [अभय एस. ओकेए, जे.] 218

13.1. जहां कोई वादी किसी संपत्ति के वैध या शांतिपूर्ण कब्जे में है और इस तरह के कब्जे में प्रतिवादी द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है या धमकी दी जाती है, एक निषेधाज्ञा सरलीकरण के लिए मुकदमा होगा। एक व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपने कब्जे की रक्षा करने का अधिकार है जो निषेधात्मक निषेधाज्ञा की मांग करके एक बेहतर शीर्षक साबित नहीं करता है। लेकिन गलत कब्जे वाला व्यक्ति सही मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा का हकदार नहीं है।

13.2. जहां वादी का अधिकार विवादित नहीं है, लेकिन उसके कब्जे में नहीं है, उसका उपाय यह है कि वह कब्जे के लिए मुकदमा दायर करे और यदि आवश्यक हो, तो इसके अलावा एक निषेधाज्ञा की मांग करे। कब्जे से बाहर कोई व्यक्ति, कब्जे की राहत का दावा किए बिना, निषेधाज्ञा की राहत नहीं ले सकता है।

13.3. जहां वादी के कब्जे में है, लेकिन संपत्ति पर उसका अधिकार विवाद में है, या एक बादल के तहत है, या जहां प्रतिवादी उस पर अधिकार का दावा करता है और प्रतिवादी से बेदखल होने का खतरा भी है, तो वादी को अधिकार की घोषणा और निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के लिए मुकदमा करना होगा। जहां वादी का अधिकार संदेह के घेरे में है या विवाद में है और वह कब्जे में नहीं है या कब्जा स्थापित करने में सक्षम नहीं है, अनिवार्य रूप से वादी को घोषणा, कब्जे और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करना होगा।

14. हालाँकि, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि घोषणा के लिए प्रार्थना केवल तभी आवश्यक होगी जब प्रतिवादी द्वारा अधिकार से इनकार या वादी के अधिकार को चुनौती देने से संपत्ति पर वादी के अधिकार पर संदेह पैदा हो। कहा जाता है कि जब किसी संपत्ति पर उसके स्वामित्व में कुछ स्पष्ट दोष होता है, या जब उस पर किसी तीसरे पक्ष का कुछ प्रथम दृष्टया अधिकार बनाया जाता है या दिखाया जाता है, तो किसी व्यक्ति के स्वामित्व पर बादल छा जाता है। घोषणा के लिए एक कार्रवाई, संपत्ति के शीर्षक पर बादल को हटाने का उपाय है। दूसरी ओर, जहां वादी के पास दस्तावेजों द्वारा समर्थित स्पष्ट अधिकार है, यदि कोई अतिक्रमणकारी बिना किसी अधिकार के दावे के या बिना किसी स्पष्ट अधिकार के कोई मध्यस्थ, केवल वादी के अधिकार से इनकार करता है, तो यह वादी के अधिकार पर संदेह पैदा करने के बराबर नहीं है और वादी के लिए घोषणा के लिए मुकदमा करना आवश्यक नहीं होगा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा पर्याप्त हो सकता है। जहाँ वादी, यह मानते हुए कि प्रतिवादी केवल एक अतिचारक है या बिना अधिकार के एक गलत दावेदार है, केवल निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करता है, और ऐसे मुकदमे में, प्रतिवादी अपने बचाव में अधिकार या अधिकार के विवरण का खुलासा करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

जो वादी के अधिकार पर गंभीर विवाद या संदेह पैदा करता है, तो वादी को वाद में संशोधन करने और वाद को घोषणा के लिए एक में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक रूप से, वह घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए एक व्यापक मुकदमा दायर करने के लिए अदालत की अनुमति के साथ खाली निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा वापस ले सकता है। निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा खारिज होने के बाद भी, वह परिणामी राहत के साथ घोषणा के लिए मुकदमा दायर कर सकता है, जहां मुकदमे में केवल कब्जे का मुद्दा उठाया गया है न कि स्वामित्व का कोई मुद्दा।” (आपूर्ति की गई रेखाएँ) 16। यह स्पष्ट है कि वादी और उसके पिता के शीर्षक के बारे में कोई मुद्दा शामिल नहीं था। ऐसा नहीं है कि उत्तरदाताओं ने अपने आप में एक शीर्षक स्थापित किया था या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दावा कर रहे थे जो शीर्षक का दावा कर रहा था। उनकी याचिका अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिकूल अधिकार की थी, जो यह मानती है कि अपीलार्थी मालिक था। जब हक के आधार पर एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद सरलीकरण में, प्रतिवादी वादी या उसके पूर्ववर्ती के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे द्वारा अपने हक की पूर्णता का अनुरोध करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी के हक के बारे में कोई विवाद है।

इसलिए, वादी को ऐसे मामले में स्वामित्व की घोषणा का दावा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस तरह के मुकदमे में शामिल एकमात्र मुद्दे यह हैं कि क्या वादी ने साबित कर दिया है कि मुकदमा शुरू होने की तारीख को वह कब्जे में था और क्या प्रतिवादी ने साबित किया है कि उसने प्रतिकूल कब्जे से अपने अधिकार को पूरा किया है। इसलिए, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के लिए स्वामित्व की घोषणा का दावा करना आवश्यक नहीं था। उनके शीर्षक पर कोई बदल नहीं था। इसलिए, सूट, जैसा कि मूल रूप से फ़ाई लेड था, बनाए रखने योग्य था। 17. केवल दो प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता थी। पहला यह था कि क्या अपीलार्थी ने यह स्थापित किया था कि मुकदमा दायर होने की तारीख को मुकदमा संपत्ति उसके कब्जे में थी। यदि अपीलार्थी इस मुद्दे को साबित करने में विफल रहता है, तो मुकदमा खारिज होने योग्य होगा। प्रतिवादियों पर प्रतिकूल कब्जे की अपनी याचिका को साबित करने का बोझ था, क्योंकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा की मांग करने वाला एक जवाबी दावा था। जवाबी दावा एक क्रॉस-सूट की प्रकृति में होता है।

18. उच्च न्यायालय ने केवल एक मुद्दे का फैसला किया है: क्या संशोधन को सीमा द्वारा बाधित किया गया था। इसलिए, उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए, उच्च न्यायालय को अन्य मुद्दों पर निर्णय लेना होगा।

19. उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून के दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो इस प्रकार हैं:

- 219

एसआरआई. के. एम. कृष्णा रेड्डी बनाम श्री। वाइन रेड्डी और ए. एन. आर. [अभय एस. ओकेए, जे.]

“1. क्या अपीलीय न्यायालय को सीमा के पहलू पर विचार किए बिना निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को उलटने में न्यायसंगत ठहराया गया था?

2. क्या अपीलीय न्यायालय के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बहिष्कृत पी-1 के आधार पर निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को उलटने में न्यायसंगत ठहराया गया था?”

हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि अनुरोध की गई कार्रवाई के कारण की तारीख और संशोधन के लिए आवेदन करने की तारीख को देखते हुए संशोधन को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं था कि मूल रूप से दायर किए गए मुकदमे को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। इसलिए, पहला प्रश्न नहीं बचता है। दूसरा प्रश्न, जैसा कि तैयार किया गया है, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। 20. चूंकि उच्च न्यायालय ने मुकदमे और जवाबी दावे के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है, इसलिए हम नियमित दूसरी अपील को उच्च न्यायालय में भेजने का प्रस्ताव करते हैं।

21. इसलिए, अपील की आंशिक रूप से अनुमति है। 10 फरवरी 2010 के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया है और 2007 की नियमित दूसरी अपील संख्या 1361 को उच्च न्यायालय में बहाल कर दिया गया है। चूंकि अपील 2007 की है, जिसे अंतिम सुनवाई के लिए

स्वीकार किया गया था, इसलिए हम उच्च न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 की उप-धारा (5) के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करके कानून के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने का निर्देश देते हैं। उच्च न्यायालय कानून के अनुसार नियमित दूसरी अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। अभियोग के संशोधन के मुद्दे को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने के अलावा, अन्य सभी मुद्दों को उच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। 22. आम तौर पर, इस न्यायालय को उच्च न्यायालयों, जो संवैधानिक न्यायालय हैं, के समक्ष लंबित किसी मामले के निपटारे के लिए कभी भी समयबद्ध अनुसूची निर्धारित नहीं करनी चाहिए। लेकिन, इस मामले में, नियमित दूसरी अपील 2007 की है। इसलिए, उच्च न्यायालय नियमित दूसरी अपील के निपटारे को आवश्यक प्राथमिकता देगा। हम इस अपील के पक्षकारों को निर्देश देते हैं कि वे सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 30 अक्टूबर 2023 को कर्नाटक उच्च न्यायालय की संबंधित रोस्टर पीठ के समक्ष सुबह 1 बजे पेश हों।

23. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

दिव्या पांडे